CMYK

Website : www.highwaychannel.in

छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक प्रसारित शाम का अखबार

हाईवे चैनल

▫ वर्ष- 28 ▫ अंक- 166 ▫ रायपुर, गुरुवार 10 जुलाई 2025 ▫ पृष्ठ-8 ▫ मूल्य- 2.50 रुपया • रायपुर • जगदलपुर से प्रकाशित RNI रजिस्ट्रेशन नं. 68139/98

नगर निगम किराए की दुकानों के लिए लाएगा ऑनलाइन सिस्टम, 10 करोड़ तक राजस्व बढ़ोतरी की उम्मीद

प्रॉपर्टी टैक्स वसूली का लक्ष्य 400 करोड़

रायपुर, 10 जुलाई (हाईवे चैनल)। प्रॉपर्टी टैक्स में ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम लागू करने के बाद रायपुर नगर निगम अब अपनी दुकानों के किराये की वसूली के लिए भी ऑनलाइन सिस्टम शुरू करने जा रहा है। निगम के पास 4 हजार दुकानें हैं, जिनसे हर साल करीब 7 करोड़ रुपये का किराया मिलता है। लेकिन वर्षों से इन दुकानों का भौतिक सत्यापन नहीं हो पाया था और कई दुकानदारों ने अपने हिसाब से दुकानों में फेरबदल कर लिया था।

राजस्व विभाग के अधिकारियों के मुताबिक, ऑनलाइन सिस्टम लागू करने से पहले 4 हजार दुकानों में से 2,035 का भौतिक सर्वे पूरा कर लिया गया है। बाकी दुकानों का सर्वे पूरा होने के बाद डेटा को सॉफ्टवेयर में अपलोड किया जाएगा। अब किराया दुकान के क्षेत्रफल और निर्धारित किराया दर के आधार पर तय किया जाएगा। किरायेदारों का नवीनीकरण और शुल्क

16 हजार से ज्यादा ओपन प्लॉट मालिक टैक्स भुगतान से बाहर

वृद्धि की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। इस प्रक्रिया से निगम को किराये की दुकानों से ही लगभग 10 करोड़ रुपये का राजस्व मिलने की उम्मीद है।

निगम इस साल कम से कम 400 करोड़ रुपये प्रॉपर्टी टैक्स वसूली का लक्ष्य लेकर चल रहा है, जिससे म्यूनिसिपल बॉन्ड लागू करने की दिशा में मजबूत कदम उठाया जा सके। इसके तहत निगम आयुक्त विश्वदीप ने हाल ही में राजस्व अमले की बैठक लेकर सभी गैर मूल्यांकित प्रॉपर्टी का वार्डवार सर्वे करने के निर्देश दिए हैं। बैठक में अपर आयुक्त यूएस अग्रवाल, उपायुक्त डॉ. अंजलि शर्मा, जसदेव सिंह बांबरा, आईटी विशेषज्ञ रंजीत रंजन सहित सभी जोनों के राजस्व अधिकारी मौजूद रहे।

शहर में 36,387 ओपन प्लॉट हैं, जिनमें से 19,752 की जानकारी निगम के पास अपडेट है, लेकिन 16,635 प्लॉट ऐसे हैं जिनके मालिकों ने अभी तक प्रॉपर्टी टैक्स नहीं चुकाया है। ऐसे में अब इन सभी प्लॉट्स को चिन्हित कर टैक्स वसूली की प्रक्रिया तेज की जा रही है। जोन के राजस्व अमले को इन्हें अपडेट करने के निर्देश दिए गए हैं।

चुनाव आयोग तय नहीं कर सकता कौन नागरिक: सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली, 10 जुलाई (न्यूज चैनल)। बिहार में मतदाता सूची के पुनरीक्षण के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज चुनाव आयोग की जमकर खिंचाई की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग तय नहीं कर सकता कि कौन देश का नागरिक है। उल्लेखनीय है कि चुनाव आयोग ने 25 जुलाई तक मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण की कवायद शुरू की है, जिसे विपक्ष दलों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि मतदाता पुनरीक्षण को बिहार चुनाव से नहीं जोड़ा जा सकता। कोर्ट ने आयोग को आड़े हाथ लेते हुए यह भी कहा कि मतदाताओं को पर्याप्त समय देने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग की खिंचाई करते हुए यह भी कहा कि आधार नंबर नागरिकता का प्रमाण नहीं हो सकता। कोर्ट ने जानना चाहा कि आगामी विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले ही यह प्रक्रिया क्यों शुरू की गई। अदालत ने इस प्रक्रिया की वैधानिकता को तो मान्यता दी, लेकिन निर्वाचन आयोग से सवाल किया कि चुनाव से ठीक पहले इसकी शुरुआत का क्या कारण है। कोर्ट ने कहा, हमारी आपत्ति आपकी प्रक्रिया से नहीं, बल्कि इसके समय से है। जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि मतदाता सूची को शुद्ध करने और गैर-नागरिकों के नाम हटाने के लिए गहन जांच में कोई खामी नहीं है। लेकिन कोर्ट ने सवाल उठाया, आपने प्रस्तावित चुनाव से कुछ समय पहले ही यह कदम उठाने का निर्णय क्यों लिया? इसके पीछे का मकसद क्या है?

ब्रेकिंग न्यूज

भूकंप के झटके से हिली दिल्ली- एनसीआर की धरती

नई दिल्ली, 10 जुलाई (न्यूज चैनल)। दिल्ली और आस-पास के इलाकों में गुरुवार सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिससे लोगों में भारी दहशत फैल गई। लोग झटकों के बाद लोग घरों और दफ्तरों से बाहर निकले। भूकंप सुबह 09 बजकर 04 मिनट 50 सेकंड पर आए। झटकों की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 4.4 मापी गई है। फिलहाल किसी जान-माल के नुकसान की सूचना नहीं मिली है। नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी के अनुसार, भूकंप का केंद्र हरियाणा के झज्जर में 28.63 उत्तरी अक्षांश और 76.68 पूर्वी देशांतर पर स्थित था, जिसकी गहराई 10 किलोमीटर दर्ज की गई है। भूकंप के झटके दिल्ली के अलावा नोएडा, गाजियाबाद और हरियाणा के कई अन्य शहरों में भी महसूस किए गए।

मैं पाँच साल के लिए मुख्यमंत्री हूँ : सिद्धारमैया

नई दिल्ली, 10 जुलाई (न्यूज चैनल)। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने गुरुवार को कहा कि वह अगले पांच साल तक सत्ता में बने रहेंगे, जिससे राज्य में नेतृत्व परिवर्तन की अटकलों पर विराम लग गया। एएनआई के अनुसार सिद्धारमैया ने कहा कि सीएम पद पर कोई चर्चा नहीं हुई। यह मेरा जवाब है। डीके शिवकुमार ने खुद कहा कि सीएम पद के लिए कोई रिक्ति नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आलाकमान द्वारा जो भी निर्णय लिया जाएगा, हम दोनों उसका पालन करेंगे; हम उसका पालन करेंगे। सिद्धारमैया ने कहा कि मैंने आज राहुल गांधी से मिलने के लिए समय मांगा था। अभी तक कोई सूचना नहीं मिली है। वहीं, सीएनएन-न्यूज18 से विशेष बातचीत में सिद्धारमैया ने कहा कि वह कहीं नहीं जा रहे हैं और वह पार्टी प्रभारी बने रहेंगे। सिद्धारमैया ने कहा, मैं पाँच साल के लिए मुख्यमंत्री हूँ, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। उन्होंने आगे कहा, कोई पद रिक्त नहीं है।

निकाय चुनावों में नहीं होगा कोई भी इंडिया गठबंधन : संजय राउत

नई दिल्ली, 10 जुलाई (न्यूज चैनल)।शिवसेना (यूबीटी) नेता संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र में आगामी नगर निकाय चुनावों में कोई भी इंडिया गठबंधन नहीं होगा। राउत ने कहा कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना (यूबीटी) और राज ठाकरे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना द्वारा राज्य में हिंदी थोपने वाली भाजपा सरकार के खिलाफ मिलकर लड़ने के लिए अपने मतभेदों को भुलाने के बाद, अब इन दोनों दलों पर स्थानीय निकाय चुनावों के लिए चुनावी गठबंधन बनाने का जनता का दबाव है, जो बिहार चुनावों के आसपास होने की उम्मीद है। संजय राउत ने आगे दावा किया कि मैंने यह नहीं कहा कि शिवसेना और मनसे मिलकर (स्थानीय निकाय) चुनाव लड़ रहे हैं।

बारिश ने बढ़ाई रेल यात्रियों की परेशानी, जलमग्न हुई रेल पटरी, प्रभावित हो रही ट्रेनें

रायपुर, 10 जुलाई (हाईवे चैनल)। मध्य छत्तीसगढ़ में लगातार हो रही बारिश ने जनजीवन के साथ-साथ रेल यातायात को भी बुरी तरह प्रभावित किया है. दुर्ग रेलवे स्टेशन पर रेल पटरी पानी में डूब गई है, जिससे कई ट्रेनों की आवाजाही पर असर पड़ा है और यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. मौसम विभाग के अनुसार, 10 जुलाई को मध्य छत्तीसगढ़ के एक-दो स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश की संभावना है. हालांकि, 11 जुलाई से प्रदेशभर में बारिश की गतिविधियों में कमी आने के आसार हैं.

पिछले 24 घंटों में प्रदेश में औसतन 13.2 मिमी बारिश दर्ज की गई है. अब तक कुल 343.6 मिमी वर्षा हो चुकी है, जो सामान्य से 15त्न अधिक है. केवल दुर्ग जिले में ही बीते दिन 13 सेमी बारिश रेकॉर्ड की गई. बारिश के चलते मोंगरा बांध से पानी छोड़ा गया, जिससे शिवनाथ नदी उफान पर है. नदी का जलस्तर बढ़ने से कई गांवों और शहरी इलाकों की कॉलोनियों में पानी घुसने का खतरा उत्पन्न हो गया है.

बारिश का क्षेत्रीय ब्यौरा कुछ इस प्रकार रहा- बालोद: 12 सेमी, अहिवारा: 10 सेमी, धमधा, मंदिरहसौद, गंडई: 9 सेमी, बोरई, अर्जुंदा: 8 सेमी, धरसींवा, डौंडीलोहारा, भखारा, पाटन, भिलाई: 7 सेमी, माना, मारी बंगला, रायपुर शहर, खैरागढ़: 6 सेमी, सरायपाली, आरंग, अंबागढ़ चौकी, पामगढ़, खरोरा, गोबरा नवापारा, गुंडरदेही, छुरिया, लाभांडी, मोहला, राजनांदगांव: 5 सेमी। लगातार हो रही बारिश ने एक ओर जहां खेतों और जलस्त्रोतों को लाभ पहुंचाया है, वहीं दूसरी ओर जनजीवन और यातायात व्यवस्था पर इसका नकारात्मक प्रभाव भी साफ दिखाई दे रहा है. रेलवे प्रशासन द्वारा पानी की निकासी और यातायात को सामान्य करने के प्रयास जारी हैं.

तेज रफ्तार बोलेरो ने स्कूल बस को मारी टक्कर, 12 बच्चे घायल

कोंडागांव, 10 जुलाई (हाईवे चैनल)। जिले के फरसगांव के पासंगी पेट्रोल पंप के पास आज सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक तेज़ रफ्तार बोलेरो वाहन ने एक स्कूल बस को जोरदार टक्कर मार दी। बस में कुल 20 छात्र सवार थे, जिनमें से 12 बच्चे घायल हो गए हैं। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए पुलिस और एम्बुलेंस को सूचित किया। सभी घायलों को फरसगांव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है, जहां उनका प्राथमिक उपचार किया जा रहा है। हादसे के बाद परिजनों में हड़कंप मच गया और अस्पताल परिसर में भीड़ लग गई। बच्चों की स्थिति फिलहाल स्थिर बताई जा रही है

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बोलेरो की रफ्तार बहुत अधिक थी और चालक का वाहन पर नियंत्रण नहीं रहा, जिससे यह गंभीर टक्कर हुई। फिलहाल पुलिस ने बोलेरो चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और मामले की जांच जारी है। ।

छत्तीसगढ़ को डीएमएफ संबंधी उत्कृष्ट कार्यों के लिए भारत सरकार के खान मंत्रालय ने किया सम्मानित

रायपुर, 10 जुलाई (हाईवे चैनल)। भारत सरकार के खान मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य को जिला खनिज संस्थान न्यास के अंतर्गत उल्लेखनीय कार्यों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया है। आज नई दिल्ली स्थित स्कोप कन्वेंशन सेंटर में आयोजित एक दिवसीय नेशनल डीएमएफ वर्कशॉप के दौरान केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री श्री जी किशन रेड्डी ने मुख्यमंत्री के सचिव और खनिज सचिव श्री पी. दयानंद को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया।

■ **खनन प्रभावित क्षेत्रों में विकास एवं पारदर्शिता के लिए छत्तीसगढ़ की सराहनीय पहल को मिला राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान**

खान मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना द्वारा नेशनल डीएमएफ पोर्टल में समस्त राज्यों के डीएमएफ से संबंधित डेटाबेस का संधारण किया जा रहा है। डीएमएफ के ऑडिट रिपोर्ट का राज्य डीएमएफ पोर्टल एवं नेशनल डीएमएफ पोर्टल में 90 प्रतिशत डेटाबेस पूर्णत: अपलोड किए जाने पर छत्तीसगढ़ राज्य को प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया। कार्यशाला में छत्तीसगढ़ के प्रयासों को मॉडल राज्य के रूप में प्रस्तुत किया गया और अन्य राज्यों को भी डेटा अपलोडिंग, पारदर्शिता और ज़मीनी क्रियान्वयन के अनुकरण की सलाह दी गई। उल्लखेनीय है कि नेशनल डीएमएफ कार्यशाला का आयोजन प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना एवं डीएमएफ की प्रभावशीलता को बढ़ाने और खनन क्षेत्रों में सतत एवं समावेशी विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया था। कार्यक्रम में देश के विभिन्न राज्यों से सचिव, संचालक एवं खनन प्रभावित जिलों के कलेक्टर्स शामिल हुए। उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा डीएमएफ के माध्यम से खनन प्रभावित क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, अधोसंरचना एवं आजीविका जैसे विविध क्षेत्रों में समावेशी विकास के लिए निरंतर कार्य किए जा रहे हैं। राज्य में अब तक 16,506 करोड़ रुपये की लागत से 1,01,313 विकास कार्यों की स्वीकृति दी जा चुकी है, जिनमें से 70,318 कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण किए जा चुके हैं। राज्य शासन द्वारा डीएमएफ के क्रियान्वयन में पारदर्शी और जनहितकारी दृष्टिकोण को अपनाते हुए, प्रत्येक जिले में स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप कार्यों की योजना और निगरानी सुनिश्चित की जा रही है।

डीएमएफ मद से निर्माणाधीन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के ठेकेदार को कार्य से अधिक भुगतान

जगदलपुर/सुकमा, 10 जुलाई (हाईवे चैनल)। विष्णुदेव साय की सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है और किसी भी भ्रष्टाचारी को बख्शा नही जा रहा है इसके बावजूद उनकी सरकार में कार्यरत अधिकारी कर्मचारी भ्रष्टाचार करने से बाज नही आ रहे हैं। ताजा मामला सुकमा जिले का है जहां डीएमएफ मद के 8.50 करोड़ रुपये से निर्माणाधीन स्पोर्ट्स काम्प्लेक्स(खेल परिसर) में पीडब्ल्यूडी विभाग के इंजीनियर ने 250 टन लोहा मौके पर मौजूद होना दिखाकर फर्जी मूल्याकंन कर ठेकेदार को 1.26 करोड़ रुपये का अग्रिम भुगतान करवा दिया, जबकि मौके पर 100 टन लोहा भी नही है।

■ **पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर ने कार्य स्थल पर 250 टन लोहा रिकॉर्ड कर ठेकेदार को करवा दिया 1.26 करोड़ का अग्रिम भुगतान**

बता दें कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में डीएमएफ मद की राशि से पीडब्ल्यूडी विभाग को कार्य एजेंसी नियुक्त कर 8.50 करोड़ रुपये की लागत से जिला मुख्यालय में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण ठेकेदार जे मनोज कुमार द्वारा कराया जा रहा है। उक्त कार्य अंतर्गत ठेकेदार जे मनोज कुमार को लाभ पहुंचाने के लिए साइट इंजीनियर चंदन सिंह मरकाम ने अग्रिम भुगतान के नाम पर 240420 किलो लोहा कार्य स्थल पर होना बताकर एमबी रिकॉर्ड किया और 04 जून 2025 को ठेकेदार को 12633025 रुपये का भुगतान किया गया। वहीं मौके पर 100 टन से अधिक लोहा मौजूद नही है जबकि सब इंजीनियर चंदन सिंह मरकाम के बनाए गए एमबी और मौके पर मौजूद लोहा का सत्यापन एसडीओ बीके शर्मा ने कर दिया। इस प्रकार विभागीय अधिकारियों ने डीएमएफ मद से स्वीकृत कार्य में ठेकेदार के साथ मिलकर सरकार को लाखों रुपये का चूना लगाया।

लोहा (सरिया) कम मिलने की शिकायत

आरटीआई से मिली जानकारी अनुसार पीडब्ल्यूडी सब इंजीनियर चंदन सिंह मरकाम ने अग्रिम भुगतान के लिए बनाए गए एमबी में 08 एमएम का 50040 किग्रा, 10 एमएम का 49919 किग्रा, 12 एमएम का 40280 किग्रा, 16 एमएम का 50089 किग्रा और 20 एमएम का 50092 किग्रा कुल 240420 किग्रा लोहा मौके पर होना बताया जबकि मौके पर 100 टन(100000 किग्रा) से अधिक लोहा मौजूद नहीं है। वहीं जानकरों का मानना है कि इंजीनियर ने लगभग 80 लाख रुपये का अधिक भुगतान ठेकेदार को लाभ दिलाने की मंशा से पहुंचाया।

सब इंजीनियर और एसडीओ सवालों के घेरे में, दोनो ने दिया गोलमोल जवाब

कार्य से ज्यादा भुगतान मामले में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के सब इंजीनियर चंदन सिंह मरकाम और एसडीओ बीके शर्मा सवालों के घेरे में है। उन्होंने वास्तविक कार्य से अधिक की एमबी रिकॉर्ड कर उसका भुगतान ठेकेदार जे मनोज कुमार को कर बड़ा लाभ पहुंचाया है। इस मामले पर सब इंजीनियर चंदन सिंह मरकाम ने कहा कि ठेकेदार लोहा को ट्रक में लाया था जिसके बाद उसे सुरक्षित स्थान रखने ले गया। वहीं कितने गाड़ी ट्रक में लोहा था कि सवाल पर सब इंजीनियर ने डायरी देख कर बता पाऊंगा कहकर फोन रख दिया। वहीं एसडीओ बीके शर्मा ने कहा कि निर्माणाधीन कोर्ट भवन और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में लोहा को देखकर सत्यापन किया था बाकी रिकॉर्ड एमबी के अनुसार सारी जानकारी सब इंजीनियर ही दे पाएंगे।

CMYK